International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS) Volume 35, Issue 04 and Publication Date: 2nd June, 2023
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

लघु एवं कुटीर उद्योगों का ग्रामीण विकास में योगदान : रोजगार वृद्धि के विशेष संदर्भ में

सुष्मिता कुमारी
शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, बी. एन. एम. यू., मधेपुरा, बिहार

सार

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास भारत की आत्मा गांव के विकास पर आश्रित है और ग्रामीण विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी कृषि के विकास पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि जो राष्ट्रीय आय में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है वह न्यूनतम उत्पादकता से प्रभावित है। भारत जैसा कि कृषि प्रधन देशों में से एक है उसी जनसख्या की 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है।, परन्तु पिफर भी भारतीय कृषि की दशा लाभप्रद नहीं कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के द्वारा कृषिकों अथवा ग्रामीण जनता को अध्कि लाभान्वित करते हुए औद्योगीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है।

विस्तार

जिस समय पश्चिमी यूरोप में जो कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली का जन्म स्थान है, असभ्य जातियाँ रहा करती थी, उन्हीं दिनों भारत अपने शासकों के ध्न, वैभव और कारीगरों के कौशल के लिए प्रसि(था और इसके बहुत समय बाद में भी, जबकि पश्चिम में व्यापारी, साहसियों ने पहली बार भारतीय भूमि पर पैर रखा। इस देश का औद्योगिक विकास यदि यूरोप के अध्कि उन्नत देशों की तुलना में श्रेष्ठ नहीं था, तो वह घटिया भी नहीं था। प्राचीनकाल में भारत औद्योगिक क्षेत्रा संसार का अग्रणी देश माना जाता था। निःसंदेह यहाँ बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, किंतु इसके लघु एवं कुटीर उद्योग विश्व विख्यात थे। इसके कारण भारत को विश्व की औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। हमारे देश की निर्मित वस्तुएँ विश्व के अध्किांश देशों में विक्रय के लिए जाती थी तथा बहुत लोकप्रिय थी। प्रमुख उद्योगों में कपड़ा, लोहा, कागज, कांच जहाजरानी तथा कलात्मक वस्तुओं को उत्पादन मुख्य था। भारतीय उद्योगों का इतिहास हमारे गौरवपूर्ण अतीत के प्रमाणों से भरा पड़ा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्रा जातक ''कहानियाँ तथा मिलिन्द पान्ह'' आदि ग्रंथों में भारतीय औद्योगिक स्थिति का स्पष्ट संकेत मिलता है। भारतीय सूतीवस्त्रा उद्योग तो अपने कला के सीमा तक पहुँच गया था, जिसके प्रमुख केन्द्र थे – ढ़ाबा, मछलीपट्टम, ठारोमंडल, गुजरात तथा सिंुधाटी, किंतु हमारी भारतीय उद्योगों की यह गौरवपूर्ण स्थिति सदैव नहीं बनी रही। इन उद्योगों पर पतन की छाया मुगल काल में ही पड़नी प्रारंभ हो गयी थी, लेकिन वास्तविक पतन तो उस दिन से प्रांरभ होता है, जिस दिन यूरोपीय व्यापरियों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गयी थी। अंग्रेजो की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इस देश में ऐसे साध्नों से कार्य किया, जिसके अनुसार यहाँ के व्यापार व उद्योग दोनों ही नष्ट हो गये और रही–सही कमी की पूर्ति

International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS) Volume 35, Issue 04 and Publication Date: 2nd June, 2023
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति तथा मशीनों द्वारा निर्मित सस्ते पदार्थो के भारतीय बाजारों में आने से पूरी हो गयी।

भारतीय स्वतंत्राता संग्राम के दिनों में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने मुख्य रुप से राष्ट्रपिता महात्मागांधी ने स्वतंत्राता आंदोलन के साथ–साथ खादी आंदोलन के रुप में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर महत्व दिया। उनका विचार था किग्रमायोग की स्थापना भारत के नव–निर्माण की प्रथम शर्त है। गाँधी जी के शब्दों में ''भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योगों में निहित है।'' अर्थात् भारतीय गांवों की समृ(एवं पुननिर्माण ग्रामयोग के माध्यम से ही संभव है। उनका स्पष्ट विचार था कि ''तुम गांवों का पुननिर्माण नहीं कर सकते जब तक की तुम ग्रामीण जीवन को उसके पुरातन दस्तकारी के संदर्भ में जागृत नहीं करते। भारतीय किसान तभी पुनर्जागृत किया जा सकता है, जब वह अपनी दस्तकारी पुनः प्राप्त नहीं कर लेते तथा अपनी आवश्यकताओं के लिए गांव पर निर्भर हो न कि शहरों पर, जैसा कि वह आज शहरों पर निर्भर होने को साध्य है।'' आज जब कि देश ने औद्योगीकरण की विशाल योजनाएँ बनायी है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की महत्ता में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ा है बल्कि कुछ सीमा तक उनका महत्व और भी बढ़ गया है।

सामान्यतया लघु उद्योग एक प्रकार से नयी शब्दावली है। भारत में स्वतंत्राता से पूर्व ग्राम एवं लघु उद्योग या जिसे कभी–कभी ग्राम्य एवं कुटीर उद्योग भी कहते में उन सभी प्रकार के उद्योगों को सम्मिलित किया जाता था जो मुधमक्खी पालन से लेकर लाह की खेती, हाथ से कताई एवं बुनाई, लकड़ी के खिलौनों से लेकर ताले एवं लोहे की अलमांरियों तक पफैले हुए थे। वास्तव में लघु एवं कुटीर उद्योग शब्दावली का अलग–अलग प्रयोग पश्चिमी विचारों के बड़े उद्योगों के समानान्तर शब्दावली के रुप में हुआ है। कुटीर उद्योगों के रुप में जा सकता है। 1937 में जब राज्यों में पहली बार कांग्रेस सरकारें बनी, उस समय थोड़ा समय इन उद्योगों की तरपफ गया, परन्तु वह समय इतना अनिश्चित एवं अल्प था कि निश्चित तौर पर बहुत स्पष्ट रुप कुछ परिणाम निकलने की आशा नहीं थी।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत औद्योगीकरण में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व एवं भूमिकाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। खासकर भारत एवं बिहार जैसे पिछड़े राज्य की परिप्रेक्ष्य में इसे दिखाने का प्रयास किया गया।

रोजगार में वृ(

ज्ञातव्य हो कि औद्योगीकरण आज के वैज्ञानिक वर्ग की प्रमुख पुकार और आवश्यकता है। बिना औद्योगीकरण के आज के इस वैज्ञानिक दौर के धुन में कोई भी देश विकास की पराकाष्ठा पर नहीं पहुँच सकती है। परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि औद्योगिक विकास पूर्ण तभी होता जब लघु एवं कुटीर उद्योग कापफी विकसित हों, क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार का एक महत्वपूर्ण समायोजक क्षेत्रा है।[1]

1929–30 की महान मंदी का यह अनुभव है कि मंदीकाल का सबसे बड़े पैमाने के उद्योगों पर बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योगों में औद्योगिक केन्द्रों पर

International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS) Volume 35, Issue 04 and Publication Date: 2nd June, 2023
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

भारी मात्राा में लोन एकत्रिात करते है और जब मंदी आती है तो ऐसे केन्द्रों पर भारी मात्राा में बेरोजगारी आती है। परन्तु लघु एवं कुटीर उद्योागें में श्रमिक स्वयं मालिक होते है। और वे देश के विभिन्न क्षेत्राों में बिखरे होते है। ऐसे लघु उद्योगों के मालिकों को सहायक रुप में कृषि व्यवसाय भी होती है, जिसके कारण मंदीकाल में उन्हें बेरोजगारी का सामना करना नहीं पड़ता है और उनमें रोजगार स्थायित्व बनी रहती है, वहीं दूसरी और रोजगार की सृजन भी होती है।

खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ भ्रम की बहुलता और पूँजी की न्यूनता है यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार के महत्वपूर्ण साध्न है। हमारे देश में ग्रामीण उद्योगों द्वारा सन 1964–65 में लगभग 3.919 लाख लोगों को पूर्णकाल के लिए तथा 21.457 लाखा लोगों को अल्पकाल के लिए रोजगार उपलब्ध करायी गयी तथा लगभग 23.92 करोड़ रुपयों की मजदूरी प्रदान की गयी। दूसरी योजना की अपेक्षा तीसरी योजना में उन उद्योगों की प्रगति अध्कि संतोषजनक रही। सन् 1950–51 में लघु उद्योगों में लगभग 1.15 करोड़ लोग लगे हुए थे। जबकि कारखाना संस्थानों में केवल 30 लाख लोग लगे हुए थे। सन् 1957–58 में लघु एवं कुटीर उद्योगों में 2 करोड़ लोगों को काम दिये गये। जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में केवल 30 लाख लोग लगे हुए थे। भारत में लगभग 7 प्रतिशत लोग लघु एवं कुटीर उद्योगों में लगे हुए है। केवल हथकरघा उद्योग में लगभग 50 लाखा लोग लगे हुए थे। इस प्रकार रोजगार की दृष्टि से इन उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण है।[2]

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की संख्या एवं उसमें लगे रोजगार की तालिका संख्या 3.1 से स्पष्ट कर सकते है।

तालिका संख्या–3.1
भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या[3]

वर्ष	*लघु एवं कुटीर उद्योगों की संख्या ;लाख मेंद्ध*	*रोजगार ;लाख मेंद्ध*
1973–74	*4.2*	*39.7*
1991–92	*20.82*	*129.80*
1995–96	*27.24*	*151.61*
1999–2000	*32.25*	*178.50*
2000–2001	*33.30*	*183.80*

इस तरह तालिका संख्या 3.1 से स्पष्ट है कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की संख्या 1973–74 एवं 2000–2001 के बीच बढ़ी है। परंतु इसकी बढ़ने की प्रवृत्ति धीमी है। उसी तरह इस क्षेत्रा में जहाँ 1973–74 में 39.7 लाख लोग रोजगार रत थे, वह 2000–2001

में बढ़कर 183.80 लाख हो गये। इस तरह रोजगार में वृ(की यह प्रवृत्ति को भी अध्कि संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, पिफर भी भारत जैसे देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार प्रदान कर रही है, जो हमोर श्रम बाहुल्य देश के लिए कापफी लाभप्रद एवं उपयोगी माना जायेगा।

भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या में लघु एवं कुटीर उद्योगों में सर्वाध्कि मनीपुर में 9. 16 प्रतिशत भ्रमिक कार्यरत है। जबकि इस दृष्टि से द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है जहाँ 7.30 प्रतिशत कार्यशील श्रमिक इस क्षेत्रा में लगे हुए है। भारत में राज्यवार घरेलू एवं लघु उद्योगों में कार्यशील जनसंख्या का रोजगाररत श्रमिकों की संख्या की वर्ष 2001 में तालिका संख्या 3.2 से दिखा सकते है।

तालिका संख्या–3.2
राज्यवार घरेलू एवं लघु उद्योगों में लगे श्रमिक : में ;वर्ष 2001द्ध[4]

क्र.सं.	*राज्य*	*घरेलू एवं लघु उद्योगों में लगे श्रमिक : में*
1.	*जम्मू–काश्मीर*	*6.22*
2.	*हिमाचल प्रदेश*	*1.68*
3.	*पंजाब*	*3.36*
4.	*चंडीगढ़*	*1.04*
5.	*उत्तरांचल*	*2.23*
6.	*हरियाणा*	*2.47*
7.	*दिल्ली*	*2.95*
8.	*राजस्थान*	*2.74*
9.	*उत्तर प्रदेश*	*5.33*
10.	*बिहार*	*3.87*
11.	*सिक्किम*	*1.23*
12.	*अरूणाचल प्रदेश*	*0.86*
13.	*नागालैंड*	*2.13*
14.	*मणिपुर*	*9.16*
15.	*मिजोरम*	*1.40*
16.	*त्रिापुरा*	*2.90*
17.	*मेघालय*	*1.88*
18.	*असम*	*3.44*
19.	*प0 बंगाल*	*7.30*
20.	*झारखंड*	*4.15*
21.	*उड़िसा*	*4.83*
22.	*छतीसगढ़*	*2.08*

क्र.सं.	*राज्य*	*घरेलू एवं लघु उद्योगों में लगे श्रमिक : में*
23.	*मध्य प्रदेश*	*3.92*
24.	*गुजरात*	*1.87*
25.	*दमन एवं दीव*	*1.58*
26.	*दादर एवं नगर हवेली*	*0.73*
27.	*महाराष्ट्र*	*2.49*
28.	*आन्ध्र प्रदेश*	*4.50*
29.	*कर्नाटक*	*3.98*
30.	*गोवा*	*2.70*
31.	*लक्ष्यद्वीप*	*5.93*
32.	*केरल*	*3.54*
33.	*तमिलनाडु*	*5.24*
34.	*पांडिचेरी*	*1.78*

तालिका संख्या 3.2 से स्पष्ट है कि बिहार में कुल कार्यशील जनसंख्या का 3.87 प्रतिशत भ्रमिक रोजगार प्राप्त किये हुए है जबकि सबसे कम दादर एवं नगरहवेली में मात्रा 0. 73 प्रतिशत कार्यशील जनंसख्या इसमें संलग्न है। जबकि जम्मूकश्मीर, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, प0बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, लक्ष्यद्वीप, तमिलनाडु इत्यादि। राज्य ऐसे है जहाँ बिहार राज्य की तुलना में अधिक कार्यशील जनसंख्या लघु एवं कुटीर उद्योग में कार्यरत है।

बिहार के जमुई जिला एक ऐसा जिला है जहाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों में कार्यशील श्रमिकों की संलग्नता सर्वाधिक 20.78 प्रतिशत है। बिहार में जिलावार लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोजगार रत कार्यशील जनसंख्या की प्रतिशीतला को तालिका संख्या 5.3 से दिखा सकते है।

तालिका संख्या–3.3
जिलावार घरेलू एवं लघु उद्योगों में लगे श्रमिक : में ;वर्ष 2001द्ध[5]

क्र.सं.	*जिला*	*घरेलू एवं लघु उद्योगों में लगे श्रमिक : में*
1.	*प0 चम्पारण*	*2.63*
2.	*प0 चम्पारण*	*2.73*
3.	*शिवहर*	*2.28*
4.	*सीतामढ़ी*	*3.26*
5.	*मुधबनी*	*3.33*
6.	*सुपौल*	*2.40*
7.	*अररिया*	*1.83*

क्र.सं.	*जिला*	*घरेलू एवं लघु उद्योगों में लगे श्रमिक : में*
8.	*किशनगंज*	*1.93*
9.	*पूर्णियां*	*1.68*
10.	*कटिहार*	*2.45*
11.	*मधेपुरा*	*1.74*
12.	*सहरसा*	*2.06*
13.	*दरभंगा*	*4.09*
14.	*मुजफ्फपफरपुर*	*3.28*
15.	*गोपालगंज*	*2.52*
16.	*सीवान*	*3.45*
17.	*सारण*	*3.86*
18.	*वैशाली*	*4.02*
19.	*समस्तीपुर*	*4.12*
20.	*बेगुसराय*	*7.06*
21.	*खगड़िया*	*2.49*
22.	*भागलपुर*	*7.43*
23.	*बांका*	*4.62*
24.	*मुंगेर*	*4.40*
25.	*लखीसराय*	*2.46*
26.	*शेखपुरा*	*3.10*
27.	*नालंदा*	*4.54*
28.	*पटना*	*3.77*
29.	*भोजपुर*	*3.74*
30.	*बक्सर*	*3.73*
31.	*भभुआ*	*3.34*
32.	*रोहतास*	*3.69*
33.	*जहानाबाद*	*3.84*
34.	*औरंगाबाद*	*4.00*
35.	*गया*	*3.91*
36.	*नवादा*	*3.67*
37.	*जमुई*	*20.78*
बिहार		*3.87*

तालिका संख्या 5.3 से स्पष्ट है कि बिहार में वर्ष 2001 में औसतन 3.87 प्रतिशत कर्मचारी या कार्यशील श्रमिक रोजगार रत है, जबकि दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय,

भागलपुर, बाँका, मूंगेर, नालंदा, औरंगाबाद, गया, जमुई, इत्यादि जिले ऐसे है जहाँ बिहार की औसतन कार्यशील जनसंख्या से अधिक जनसंख्या लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोजगाररत है। यद्यपि लघु एवं कुटीर उद्योगों में इतनी कम कार्यशील श्रमिकों की सलंग्नता बिहार जैसे जनाध्क्यि वाले राज्य के लिए शोभनीय नहीं है पिफर भी कार्यशील जनसंख्या की इतनी संलग्नता बिहार के मैदानी भागों के लिए एक शुभ संकेतक है। इस तरह बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगारी का सृजन करती है तो दूसरी ओर लोगों को अधिक रोजगार भी देती है तथा अर्धरोजगारी की स्थिति में सुधर भी लाती है। इससे उनकी आय भी बढ़ती है वही कारण है कि देश में पफैक्ट्री क्षेत्रा की 8 प्रतिशत की स्थिर पूँजी तथा 28 प्रतिशत उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योग से होता है।

स्पष्ट है कि औद्योगीकरण का बिहार जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के लिए आर्थिक विकास की दृष्टि से कापफी महत्वपूर्ण स्थान है। जिसकी प्राप्ति में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका कापफी सराहनीय है।

—: संदर्भ :—

1. *डॉ0 म0 म0 भालेराव, भारतीय कृषि अर्थशास्त्रा, पृ0 सं0 328.*
2. *वही, पृ0 सं0 328.*
3. *योजना, जून, 2001, पृ0 सं0 7 एवं केशव दास वैकल्पिक आर्थिक सर्वे 2000—2001, पृ0 सं0 58.*
4. *सेंसस ऑपफ इंडिया, 2001, सीरीज, 11, बिहार पेपर—3, पृ0 सं0 32.*
5. *वही, पृ0 सं0 365.*